

# प्र.मंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने अपने आधिकारिक आवास पर प्र.मंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया

माँसको, 9 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्र.मंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने के बाद एक्स पर लिखा, 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल पुरस्कार प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे भारत की जनता को समर्पित करता हूँ।'

रूस में प्र.मंत्री मोदी को सम्मानित किए जाने का वीडियो क्लिप सामने आया है। इसमें मोदी को राष्ट्रपति पुतिन कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। पहले वह उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोसल का आगे की दिखाते हुए इशारा करते हैं। इसके बाद उन्हें पीछे की तरफ कुछ दिखाते हैं। इस दौरान मोदी को पुतिन उन्हें मिले सम्मान में लगे खास तरह के संकेतों का मतलब बता रहे होते हैं। मालूम हो कि साल 1698 में योशू के प्रथम प्रचारक और रूस के संरक्षक सेंट सेंट एंड्रयू के सम्मान में जार पीटर द ग्रेट की

रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए दिया है।

बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में रूस-भारत संबंधों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल रूस और भारत के बीच व्यापार 66 प्रतिशत बढ़ गया है और इस वर्ष की पहली तिमाही में आपसी व्यापार में 20 प्रतिशत की और बढ़ोतरी हुई है।

ओर से स्थापित 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोसल' रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।

इससे पहले प्र.मंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से लंबी बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने अपील की कि यूक्रेन के युद्ध में मासूमों की मौत बहुत ही पीड़ाजनक होती है। युद्ध भूमि से समाधान नहीं निकला करते हैं, इसलिए संवाद और कूटनीतिक माध्यम से समाधान खोजे जाने चाहिए। मोदी ने भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान यह बात खुल कर कही। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के

सुझावों की सराहना की। बैठक में दोनों देशों ने किफायती ऊर्जा, उर्वरक व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक में भारत ने रूस में आतंकवाद की घटनाओं की कड़ी निंदा की। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में रूस-भारत संबंधों में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की सराहना की। उन्होंने जिक्र किया कि पिछले साल रूस और भारत के बीच व्यापार 66 प्रतिशत बढ़ा। 2024 की पहली तिमाही में 20 प्रतिशत और बढ़ गया। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में निकटता से सहयोग करते हैं।



प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने "सेंट एंड्रयू द एपोसल" सम्मान मोदी को प्रदान किया। यह सम्मान प्र.मंत्री मोदी को दोनों देशों के आपसी रिश्तों को बढ़ावा देने में असाधारण भूमिका निभाने के लिए दिया गया।

# जे.डी.यू. केन्द्रीय बजट से 30 हजार करोड़ रु बिहार को देने की मांग कर रही है

मोदी सरकार के सबसे बड़े साथी- टी.डी.पी. ने भी 12 बिलियन डॉलर की भारी रकम की मांग की है, आंध्र प्रदेश के लिए

नई दिल्ली, 9 जुलाई। केंद्र सरकार आगामी 23 जुलाई को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। इस बजट को जारी करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सरकारी कर्ज पर अंकुश लगाते हुए सभी राज्यों की सरकार की मांगों को संतुलित करना होगा। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में परियोजनाओं के लिए मदद के लिए केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है। यह गठबंधन सरकार के लिए एक परीक्षा साबित हो सकती है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि जनाता दल (यूनाइटेड) के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को बिहार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ

एन.डी.ए. के दोनों गठबंधन दलों की मांगों को मिला दे तो यह सरकार के वार्षिक खाद्य सिल्विडी बजट 2.2 ट्रिलियन रुपये के आधे से भी ज्यादा के बराबर है। इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी पर राजकोषीय दबाव बढ़ गया है।

है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि इस साल राज्य को कितना बजट आवंटित किया जाएगा। ब्यूजटिंग न्यूज ने पिछले सप्ताह के रिपोर्ट की माने तो केंद्र की गठबंधन सरकार में मोदी के सबसे बड़े साथी-तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू ने भी भारी रकम की मांग की है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए अगले कुछ सालों में 12 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता के लिए अनुरोध किया है। दोनों गठबंधन दलों की मांगों को मिला दे तो यह सरकार के वार्षिक खाद्य सिल्विडी बजट 2.2 ट्रिलियन रुपये के आधे से भी ज्यादा के बराबर है। इससे यह साफ पता

चलता है कि मोदी पर राजकोषीय दबाव बढ़ गया है। प्र.मंत्री पर अपने साथियों की मांगों के साथ साथ सरकारी लोन में कमी ला कर संतुलन बनाने का भी दबाव है। हालांकि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को इस बार रिजर्व मुनाफा दे और टेक्स कलेक्शन में वृद्धि के बाद इस साल के बजट में सरकार के पास कुछ छूट है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी और सरकार बनाने के लिए जदयू और टीडीपी के समर्थन पर निर्भर है। बीजेपी के दोनों सहयोगी चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें अपने राज्यों में अधिक उधार लेने की इजाजत दे।

## सचिन पायलट ने टोंक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके कहने पर अगर सरकार आख मूंद लेगी और यह गैर कानूनी कार्यवाई होती रहेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर के कटुआ में सेना पर हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

बालिका सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोहना के भवन का निर्माण विधायक कोटे की राशि से हुआ है, जिसकी लागत 4 करोड़ 49 लाख थी। विद्यालय के प्रिंसिपल ने दिव्यांगों के लिए लिफ्ट, सी.सी.टी.वी. कैमरे, वॉटर कूलर सहित पायलट को स्कूल के लिए आवश्यक बीस बिंदुओं की सूची दी। पायलट ने सभी कार्यों को अपने विधायक मद से पूरा कराने की घोषणा करते हुए कहा कि, टोंक के विकास के लिए, विशेषकर शिक्षा विभाग के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

सचिन पायलट ने 4 करोड़ 49 लाख की लागत से बने राजकीय बालिका सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोहना के लोकार्पण समारोह में कहा कि साढ़े चार करोड़ की लागत से यह स्कूल भवन बना है। स्कूल में और भी आवश्यक सामान व सुविधाओं बीस बिंदुओं की लिस्ट प्रिंसिपल ने दी है। वो

## ए.डी.जे....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सब भी बालिकाओं की पढ़ाई के हित में दूंगा। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसी भी तरह के साधन संसाधनों की कमी नहीं आने दूंगा। लोकार्पण कार्यक्रम में सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कहा कि शिक्षा विकास का सबसे बेहतर माध्यम है। बालिकाओं की शिक्षा में उनकी ओर से भी हर संभव मदद की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, पूर्व

## कांग्रेस प्र.मंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग करेगी

लेकर हाईकोर्ट की परीक्षा सेल को योग्य विधिवेत्ताओं व प्रोफेसर्स की कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कमेटी को भी निर्देश दिए थे कि वह प्रश्न पत्र की लंबाई व प्रश्न हल करने को देखने के लिए स्वतंत्र रहेगी और हाईकोर्ट की परीक्षा सेल चार्ट के जरिए कॉपीयों में कमेटी की ओर से दिए गए अंक और मौजूदा अंकों का तुलनात्मक अध्ययन कर हाईकोर्ट को बताएगी। इसे हाईकोर्ट प्रशासन ने एस.एल. पी. के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है और कमेटी की रिपोर्ट में भी परीक्षा को सही होना बताया है। गौरतलब है कि ए.डी.जे. भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अस्थायी प्रदीप मलिक व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती परीक्षा के पेपर ज्यादा लंबे थे और साक्षात्कार में चार गुणा अभ्यर्थियों की बजाय केवल चार अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया, जबकि भर्ती में 779 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना गया था। इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को बोनस अंक देकर वकील कोटे के सभी खाली 81 पदों को भरा जाए।

# कांग्रेस प्र.मंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग करेगी

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर प्र.मंत्री मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ को पत्र भी लिखा है। रमेश ने यह चिट्ठी सोशल मीडिया चैनल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "ना-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉ. हामिद अंसारी के खिलाफ उनके अपमानजनक बयानों के लिए विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024

दरअसल, प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए गत 2 जुलाई को लोकसभा में कहा, 'चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी। साथ ही, सभापति का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे।

दरअसल, प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कुछ अहम बातें कही थीं। उन्होंने 2 जुलाई को लोकसभा में कहा, 'चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी। साथ ही, सभापति

अंसारी अगस्त 2012 से अगस्त 2017 तक राज्यसभा के सभापति रहे। दरअसल, प्र.मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कुछ अहम बातें कही थीं। उन्होंने 2 जुलाई को लोकसभा में कहा, 'चाहे विपक्ष कितनी भी संख्या का दावा करे, जब हम 2014 में आए तो राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी। साथ ही, सभापति

का झुकाव कुछ हद तक दूसरी तरफ था, लेकिन हम गर्व के साथ देश की सेवा करने के अपने संकल्प से नहीं डिगे। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी भी बाधा से न तो मोदी डरेंगे और न ही यह सरकार डरेगी। हम जिन संकल्पों को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, उन्हें पूरा करेंगे।

# 'कहीं ऐसा ना हो कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ जाये'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुये कहा कि, आतंकवाद बंद हो जाना चाहिये नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जायेगा

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कटुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत करने वाले अब्दुल्ला ने खुलकर कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं हो सकती। पहले इसे बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर पूरी दुनिया को दबाव बढ़ाना चाहिए कि वह आतंकवाद को बंद करे वरना बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर

इसी तरह आतंकवाद चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि हमें युद्ध पर उतरना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने कहा, यह आतंकवाद किसी की मदद नहीं करेगा। अगर वह मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी (पाकिस्तान) यह समझला है कि इससे कोई तब्दीली आएगी तो वह नहीं होगा। वे फेल हो जाएंगे। आज पांच जवानों ने शहादत दे दी है। पांच अस्पताल में गंभीर हैं। मुझे इससे तो डर है कि कहीं हम लोगों में लावा इतना भर जाए कि हमें लड़ाई पर आना पड़े। उनको ये देखना

चाहिए वे पहले ही बर्बाद हो गए हैं। लड़ाई दोनों मुल्कों में तबाही हो जाएगी। इसको बंद करो। आतंकवाद को बंद करो। सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। उन्होंने कहा, कोई भी दुनिया का मुल्क इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। ये जो कर रहे हैं इससे उनको मिलेगा क्या। आज उन जवानों के घरों में मातम हो रहा होगा। वे कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। ये मातम आए।

फारुक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी (पाकिस्तान) सोच क्या है। इससे कोई भी होगा जब ये सब बंद होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। वक्त आ गया है कि अगर हमें दोस्ती चाहिए तो उसकी राह बनानी होगी। आतंकवाद उस रास्ते की तरफ नहीं है। उनको आतंकवाद पर सख्त कदम उठाने चाहिए। फारुक अब्दुल्ला ने कहा, आज ही नहीं सालों साल से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या वे चाहते हैं कि उनके घरों में भी मातम आए।

भी आगे नहीं आएगा। इससे वे पीछे जाएंगे। देर होने से पहले उन्हें बंद करना चाहिए। पूरी दुनिया को इस देश पर दबाव बढ़ाना चाहिए और बताया चाहिए यह शांति का नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है और इसको तुरंत बंद करना चाहिए।

बता दें कि सोमवार को कटुआ में सेना के काफिले पर आतंकीयों के झुंड ने हमला कर दिया था। आतंकीयों ने वाहनों को घेर लिया और फिर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। घात लगाकर किए गए हमले में पांच जवान शहीद हो गए और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस शिष्टमंडल में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य सभा सदस्य शंभू शरण पटेल, लोक सभा के महासचिव, उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव पी.सी. मोदी शामिल हैं। लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव अंजनी कुमार शिष्टमंडल के सचिव हैं।

दसवें ब्रिक्स संसदीय मंच का मुख्य विषय 'समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका' है।

## 'बिहार व बंगाल जैसे राज्यों में मुस्लिमों की आबादी अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है'

नई दिल्ली, 9 जुलाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) से जुड़ी एक पत्रिका ने देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ 'जनसांख्यिकीय असंतुलन' बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है। 'ऑर्गेनाइज्ड' सांसाधनिक के ताजा अंक में प्रकाशित सांसाधनिकीय में जनसंख्या के लिहाज से क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए नीतिगत हस्तक्षेप की वकालत की गई है।

## चार दिन में दूसरी बार राहुल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) साथ ही, एक सीट (कानपुर में सीएसएम) इसलिये खाली हुई है कि उस सीट के विधायक को भ्रष्टाचार के एक केस में दोषी ठहराया गया है। अन्य सीटों, जहाँ उपचुनाव होने हैं, इस प्रकार हैं- प्रयागराज में फूलपुर, अलीगढ़ में खैर, गाजियाबाद शहर, मिर्जापुर में महुआ, मुजफ्फरनगर में मीरपुर, फैजाबाद में मिल्कीपुर, मैनपुरी में करहल, अम्बेडकर नगर में कथेरी तथा मुरादाबाद में कुन्द्रकी। वर्ष 2022 के चुनावों में, इनमें से पाँच सीटों पर भाजपा तथा उसके गठबंधन-पार्टनरों की जीत हुई थी तथा शेष पाँच सीटों इण्डिया गठबन्धन के खाते में गई थीं। इन उपचुनावों के परिणामों का योगी आदित्यनाथ सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं होगा। जैसा कि सामान्य ट्रेंड रहा है, राज्य के उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल की ही विजय हुई है। फिर भी, इन उपचुनावों से एक बड़ी राजनीतिक प्रतीकात्मकता जुड़ी हुई है। एन.डी.ए. तथा इंडिया गठबन्धन इन सीटों को जीतने के लिये एडी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक सीट के लिये दो मन्त्री नियुक्त कर रखे हैं तथा

## अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।

क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या से सटी हुई सीट है और भाजपा इस सीट पर जीतती है तो उसकी अयोध्या में प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो जाती है जो फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद काफी गिर सी गयी थी।

## भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।

## भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।

## भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।

## भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।

## भारत-रूस संवाद से पहले...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अतः मोदी का पुतिन को गले लगाया यह मैसेज भी दे रहा था कि भारत की विदेश नीति भारत के हितों पर निर्भर करती है केवल थ्योरेटिकल सिद्धांतों पर नहीं।